



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2374]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2012/अग्रहायण 21, 1934

No. 2374]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2012/AGRAHAYANA 21, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2875(अ).—विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मेघालय के हन्नीवट्टैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच एन एल सी) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सुदर्शन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में “विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा. सं. 11011/80/2012-एन. ई. V]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2012

S.O. 2875(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Sudershan Kumar Misra, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) of Meghalaya as Unlawful Association.

[F. No. 11011/80/2012-NE. V]

SHAMBIU SINGH, Jt Secy.